भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1807

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

कोयला परिवहन संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण

1807. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में मौजूदा कोयला परिवहन संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए रेलवे के साथ तालमेल किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : तिरप और तिकक साइडिंग पर 4.93 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। तिकक कोलियरी और तिरप कोलियरी में कोयला परिवहन के लिए सड़कों का आधुनिकीकरण, जिसमें 10.70 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है, वर्तमान में चल रहा है।

(ग) : कोयला मंत्रालय असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए रेल मंत्रालय के साथ निकट समन्वय करता रहा है। कार्यों के समय पर निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट आवंटन, नई लाइन और दोहरी लाइन वाली परियोजनाओं की मंजूरी, नए ट्रेकों को शुरू करने और सतत निगरानी और अनुवर्ती कार्यतंत्र में पर्याप्त वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 25-26 में, रेल मंत्रालय ने असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली 69,342 करोड़ रु. की लागत से 777 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 12

रेलवे परियोजनाओं (08 नई लाइनें, 04 दोहरी लाइनें) को मंजूरी दी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली कुल 1,790 किलोमीटर लंबाई के 17 सर्वेक्षणों (13 नई लाइनें और 4 दोहरी लाइनें) को मंजूरी दी गई है।

(घ) : रेल परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा अनेक कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, सुविधाओं के अंतरण, सांविधिक अनुमोदन, भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल पर कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे और एक वर्ष में उपलब्ध कार्यात्मक महीनों की संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि ये कारक परियोजना स्थानों में परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अपेक्षित पूर्णता अवधि परियोजना से परियोजना में परिवर्तनशील होती है।

समय पर कार्य प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना, क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, विभिन्न स्तरों पर परियोजना के लक्ष्यों की गहन निगरानी करना और शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन और वन्यजीव स्वीकृति और परियोजना से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय करना शामिल हैं।

****